Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

आजमगढ़ जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की समस्याओं का अध्ययन

विनीता सिंह
शोधकर्ती, राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज जौनपुर
डॉ. नीता सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज जौनपुर

Article Info

Publication Issue :
January-February-2023
Volume 6, Issue 1

Page Number : 82-96

Article History
Received : 01 Jan 2023
Published : 20 Jan 2023

उद्देश्य: इस शोध पत्र का उद्देश्य आजमगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट समस्याओं का अध्ययन करना है। अध्ययन में पाया गया कि आजमगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर अधिक है, 30% से अधिक छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रापआउट के प्रमुख कारण गरीबी, माता–पिता के समर्थन की कमी, शिक्षा में रुचि की कमी और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन थे। अध्ययन से यह भी पता चला कि स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियाँ अप्रभावी थीं, केवल कुछ प्रतिशत स्कूलों ने प्रभावी रणनीतियों का उपयोग किया जैसे कि गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और शैक्षणिक कठिनाइयों वाले छात्रों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना। निष्कर्ष आजमगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और शैक्षणिक कठिनाइयों वाले छात्रों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना। प्राथमिक विद्यालयों में ड्रापआउट की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार, स्कूलों, अभिभावकों और समुदाय के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की भी आवश्यकता है।

परिचय:

शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करती है। भारत में, शिक्षा को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, और सरकार ने शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में छह साल की स्कूली शिक्षा होती है, जिसकी शुरुआत छह साल की उम्र से होती है। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह बच्चे के भविष्य के शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास की नींव रखता है। इस स्तर पर ड्रॉपआउट न केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी डालता है।

उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला भारत के उच्च ड्रॉपआउट दर वाले जिलों में से एक है। जिले में गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का एक उच्च अनुपात है, जो शिक्षा प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य आजमगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की ड्रॉपआउट समस्याओं का अध्ययन करना है। अध्ययन का उद्देश्य ड्रॉपआउट के कारणों की पहचान करना और ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों की प्रभावशीलता की जांच करना है। इस अध्ययन के निष्कर्ष आजमगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर को कम करने और सभी के लिए शिक्षा की पहुंच में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां

भारत में प्राइमरी स्कूल स्तर तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अभी भी एक संघर्ष है। सरकारी और निजी स्कूलों की एकीकृत शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है। भारत सरकार हमेशा प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने और नामांकित बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है। 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 35 मिलियन बच्चे अभी भी निरक्षर थे। एक अन्य अनुमान के अनुसार, पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले केवल 40% बच्चे ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर पाए थे। लड़कियों में अशिक्षित लड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक था। मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी लड़कों और लड़कियों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है। व्यक्तिगत गुण, समझ, भाषा की योग्यता और रचनात्मकता सभी को सरकार और स्कूल विभागों द्वारा अधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत में, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सर्वव्यापी, सुलभ पहुंच और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अवधारण, साथ ही शिक्षा में लिंग और सामाजिक उच्च और निम्न को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही, यह तथ्य कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी निरक्षर आबादी है, चिंता का कारण है। भारत में गुलामी लोगों के आर्थिक और शैक्षिक संकट के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन आजादी के बाद, भारत ने आर्थिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हासिल किया है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय व्यावहारिक रूप से ग्रह पर हर देश में शीर्ष स्थान रखते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में अनुमानित प्रभाव प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

स्वतंत्रता के बाद, शिक्षा नीति 1986 में जारी की गई थी, और छह साल बाद, 1992 में इस पर फिर से विचार किया गया था, इस सिफारिश के साथ कि जब तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष योजना विकसित नहीं की जाती, तब तक देश में हर बच्चे को शिक्षा की पेशकश की जानी चाहिए। वहां पहुंचना असंभव होगा। साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित देशों को वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। चीन, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान और अन्य जैसे पड़ोसी देशों में हमारी शिक्षा खराब स्थिति में है।

स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर बमुश्किल 12 प्रतिशत थी, लेकिन हाल की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई है। यह इस तरह से छह गुना बढ़ गया है, फिर भी यह वैश्विक साक्षरता स्तर से नीचे है।

पिछले दशक के दौरान, भारत की साक्षरता दर में 9% की वृद्धि हुई है। एक अध्ययन के अनुसार, युवाओं का एक बड़ा प्रतिशत स्कूल जाता है, लेकिन उपयुक्त आवास की कमी के कारण छोड़ देता है, जैसे कि ठंडी बारिश और गर्मी।

देश के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और अगर उनके पास भी है, तो भी पानी की गुणवत्ता खराब है। स्कूलों में अब शौचालय की व्यवस्था की गई है।

बड़ी संख्या में स्कूलों में प्रशिक्षकों की कमी है और उन्हें नियुक्त किया गया है, इसलिए छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। उनका शैक्षिक स्तर बहुत कम है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में है।

1.2 स्कूल ड्रॉपआउट कारण, परिणाम और विशेषताएं

स्कूल छोड़ने वाला यह वह घटना है जिसमें छात्र कक्षाओं में भाग लेना बंद कर देता है और स्कूली डिप्लोमा प्राप्त किए बिना शैक्षणिक प्रणाली से बाहर रहता है। यह घटना आमतौर पर लैटिन अमेरिका में देखी जाती है, यह देखते हुए कि यह उच्च विद्यालय छोड़ने की दर वाला क्षेत्र है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, स्कूल छोड़ने वालों के कुछ मुख्य कारण हैंरू कुपोषित बच्चे या वे जिन्हें गरीब वातावरण, सामाजिक बहिष्कार या कम क्षमता वाले स्कूलों के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है।

1.2.1 भारत में स्कूल ड्रॉपआउट से सम्बंधित कारक

स्कूल छोड़ने वालों की विशेषताओं को देखते हुए, संयुक्त राज्य में बच्चों और किशोरों पर व्यापक कार्य अध्ययन मूल्यवान होगा क्योंकि अध्ययन पूरा हो गया है और कई मामलों में अनुसंधान डिजाइन और विश्लेषण के लिए कठोर आवश्यकताओं का पालन करता है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य में माध्यमिक विद्यालयों

में हाई स्कूल छोड़ने वालों की संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का कानून सभी विद्यार्थियों को कम से कम 16 वर्ष की आयु तक स्कूल जाने के लिए मजबूर करता है। अधिकारियों को उन बच्चों का पता लगाने का काम सौंपा गया है जो अक्सर देश से दूर रहते हैं। यह जानकारी उन देशों में उपयोगी हो सकती है जहां बड़े बच्चों के बीच ड्रॉपआउट मुद्दा केंद्रित है।

भारतीय साहित्य के अनुसार, तालिका 1 बच्चों के स्कूल छोड़ने की पर्याप्त संभावना के निर्धारकों पर प्रकाश डालती है। प्रत्येक ड्रॉप–आउट सुविधा की दिशा और गुणवत्ता को आमतौर पर इन मानदंडों द्वारा समझाया जाता है। अमीर और विकासशील देशों में व्यावहारिक रूप से सभी उदाहरणों में, चर और स्कूल छोड़ने वालों के बीच नकारात्मक संबंध समान है। एक अपवाद है लिंगरू अमेरिका और ओ.ई.सी.डी देशों में अक्सर लड़के छोड़ते हैं जबकि विकासशील देशों में लड़कियाँ अधिकतर स्कूल छोड़ती हैं। इस तालिका के लिए विशेष अध्ययनों को परिशिष्ट में दिए गए चार्ट में सूचिबद्ध किया गया है ताकि यह पहचान करने में सहायता मिल सके कि प्रत्येक अध्ययन में संभावना की कौन से कारकों की चर्चा की गई है। व्याख्या करने की सुविधा के लिए कारक के स्रोत के आधार पर चार्ट पर दी गई संभावनाओं के कारकों को चार श्क्षेत्रों में बाँटा गया है, व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समुदाय।

प्रत्येक क्षेत्र में एक साथ प्रतीत होने वाले कारकों का समूहीकरण किया गया है। ष्व्यक्तिगतष क्षेत्र में पृष्ठभूमि संबंधी अभिलक्षण आते हैं, जैसे नामांकन के समय उनकी उम्र एवं लिंग, व्यस्क होने के पूर्व ही घर की और काम के उत्तरदायित्तव, सामाजिक सोच, महत्व एवं व्यवहार (अर्थात् एक छात्र किन मित्रों के साथ जुड़ा है और इनसे कैसे जुड़ा); स्कूल में प्रदर्शन (अर्थात् एक छात्र कितना सफल होता है) स्कूल की व्यस्तता (अर्थात् स्कूल जाने के लिए एक छात्र कितना उत्साहित रहता है या प्रेरित होता है) और स्कूल में व्यवहार (अर्थात् अनुशासन संबंधी विषय)। ष्पारिवारिक क्षेत्र में एक परिवारिक इकाई की पृष्ठभूमि संबंधी अभिलक्षण आते हैं (जैसे निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर, माता–पिता का कम शिक्षित होना) और स्कूल के साथ परिवार के आबंध के मापदंड और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के विचार पर उनकी प्रतिबद्धता (जैसे स्कूल के साथ कम संपर्क स्कूल जाने को कम महत्त्व देना)। ष्स्कूलष क्षेत्र मे संरचना संबंधी मापदंड आते हैं (जैसे स्कूल का घर से बहुत दूर होना, पर्याप्त सुविधाओं की कमी) और कार्यात्मक मापदंड (जैसे शिक्षण की गुणवत्ता में कमी, पाठ्यक्रम की संबद्धता में कमी)। अंत में, ष्सामुदायिक क्षेत्र में उस स्थान का विवरण शामिल है जहाँ से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं (जैसे शहरी या ग्रामीण, स्थिति का प्रतिकूल होना, आपातकाल या राजनीतिक रुप से दुर्बल राज्य)। दाहिनी ओर के दो कॉलम में बड़ी अक्षरों से लिखी बातें उन कारकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका उल्लेख एक तिहाई से भी अधिक समीक्षा किए गए लेखनों द्वारा किया गया है।

2. शोध विषय की पृष्ठभूमिः

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह इसमें रहकर समुदाय के साथ सद्भाव विकसित करता है। सामाजिक समरसता बहाल करने के लिए व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा इस प्रवृत्ति को संशोधित करने में मदद कर सकती है। नतीजतन, शिक्षा परिवर्तन है।

1. औपचारिक शिक्षा

2. अनौपचारिक शिक्षा

3. औपचारिकोत्तर शिक्षा

इनमें से औपचारिक शिक्षा एक साधन है जिसके द्वारा बालक में वही परिवर्तन किये जाते हैं जो सम्माज द्वारा मान्य होते हैं। विद्यालय शिक्षा द्वारा बालकों के सामाजिक गुणों को विकसित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के विकास में विद्यालय एक आवश्यक साधन है। मौलिक लक्ष्य प्राथमिक, माध्यमिक और अनिवार्य स्कूली शिक्षा के माध्यम से साक्षरता के स्तर को बढ़ाना है।

आरम्भ में प्रादेशिक्षाः सतत शिक्षा तथा बाद में औपचारिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया, किन्तु भारत सरकार इस लक्ष्य में विफल रही। इसलिए नियोजन आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षा विशेषज्ञों ने पुनः बैठक में सुझाव दिया कि सन् 1965–66 तक 6दृ11 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए शीघ्रता से प्रयास किये जाये।

भारत सरकार ने 1–8 वर्ष तक के बच्चों को पाठ्यक्रम के लिए एलीमेण्ट्री शब्द एवं कक्षा 1–5 तक स्कूली कोर्स प्राइमरी कोर्स माना।

डॉ. डी.सी. तिवारी को शिक्षा का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने 15 वर्षीय ष्पांच वर्षीय पाठ्यक्रमष् पूरा किया है। सरखी विकास (1910–1912) के अनुसार देश में बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य और अनिवार्य बनाना। उनकी मुलाकात हरदाग समिति (1929) से भी हुई थी, जिसने सिफारिश की थी कि प्रारंभिक शिक्षा कम से कम साढ़े चार घंटे की हो।

बुद्ध के घोषणापत्र (1954) ने इसका समर्थन किया, और सर चली बुच ने कहा कि इसे भारतीय शिक्षा के रूप में समझने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। इसे श्मैग्ना कार्टाश के नाम से जाना जाता है। इसी तरह, हंटर कमीशन (1982) और कोठारी आयोग (1964–66) जैसे विभिन्न आयातों ने प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त और सभी के लिए खुला बना दिया है।

अनिवार्य के साथ–साथ, छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य गतिविधियाँ प्रदान की गईं, और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया।

स्कूल छोड़ने का अर्थ है शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूली शिक्षा छोड़ना या स्कूल छोड़ना। साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि ऐसे ड्रॉपआउट ने पढ़ने और लिखने की अपनी क्षमता को पूरी तरह से खो दिया है। स्कूल छोड़ना एक कारक के बजाय व्यक्तिगत योग्यता अध्ययन निषेध का परिणाम है।

अनुसंधान की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा ही देश के फलने–फूलने और समृद्ध होने का एकमात्र तरीका है। जिस राष्ट्र में सभी बच्चों के लिए समान, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वह कभी भी मजबूत नहीं हो सकता।।

3. शोध के उद्देश्य

आजमगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की ड्रॉपआउट कठिनाइयों की जांच की गई (बुधनपुर तहसील के विशेष संदर्भ में) इस अध्ययन का उद्देश्य आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर की जांच करना और सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करना है।

- इस बारे में अधिक जानने के लिए कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र क्यों छोड़ देते हैं।
- शासकीय एवं अशासकीय प्रमाणित प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के बार–बार प्रस्थान की जाँच करना।
- प्राइमरी स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के कारणों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
- इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण विद्यालयों के शैक्षिक कारणों को देखना है।
- सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों और शहरी ग्रामीण छात्रों के समायोजन और नामांकन की स्थिति की जांच करना।
- अंतर्जातीय, अंतर–लिंग, शहरी–ग्रामीण और सरकारी गैर–सरकारी स्कूली विद्यार्थियों सहित प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्कूल छोड़ने के मुद्दे की जांच करना।
- सर्वेक्षण उपागम का उपयोग करके यह पता लगाना कि विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल क्यों छोड़ देते हैं।

4. शोध का परिसीमन

प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की कठिनाइयों के शोध के भाग के रूप में आजमगढ़ जिले को छोड़कर विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों, सरकारी और गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अध्ययन के लिए चुना गया था।

बूढ़नपुर तहसील के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड (लाक)– 03 ब्लाक ।

1– अतरौलिया

2– कोयलसा

अहरौला

बूढ़नपुर तहसील के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालयोंकी संख्या –

क्र०सं०	विकास खण्ड (ब्लाक) का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1	अतरौलिया	1–79
2	कोयलसा	1–100
3	अहरौला	1–90

5. शोध पद्धति

यह रणनीति किसी भी शोध परियोजना के लिए उपयुक्त है। शोध प्रक्रिया में वैधता, निर्भरता और निष्पक्षता अधिक महत्वपूर्ण हैं। उद्देश्य विश्लेषण के परिणाम। उन्हें फिर से सत्यापित किया जा सकता है।। यह अवश्य ध्यान रखना पड़ता है कि प्रदत्तों का संकलन उद्देश्यपूर्ण हो। इस अध्याय में विषयवस्तु क्रमशः शोध की प्रकृति कथन, चयन, उपकरण, प्रदत्तों का संकलन तथा फलांकन, सांख्यिकीय विधियों का उल्लेख एवं महासारिणी का निर्माण कर संयोजित किया गया है।

6. शोध कार्य की प्रकृतिः

अकादमिक शोध पद्धतियों को विश्लेषणात्मक–सिंथेटिक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, या सर्वेक्षण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।। ऐतिहासिक शोध के सन्दर्भ में ऐतिहासिक पद्धति एवं निया स्थितियों में प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध में इस बात का उत्तर खोजा जाता है कि यदि किसी विशेष नियंत्रित स्थिति में सम्बद्ध कार्य किया गया तो उसका परिणाम क्या होगा ? सर्वेक्षण विधि में प्रदत्तों का संकलन एवं परिणाम विश्लेषण किया जाता है। यह पद्धति अधिक प्रयोग में लायी जा रही है। इसी पद्धति का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि में प्रवत्तों का संकलन एवं परिणाम विश्लेषण किया जाता है।

सर्वेक्षण अनुसंधान में छोटी या बड़ी जनसंख्या में से प्रतिदर्शो का चयन कर अध्ययन किया जाता है। इसमें समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक चरों के अन्तर्सम्बन्धों, विवरणों एवं सापेक्ष प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है।

जार्ज मोले इसे विस्तृत वर्गीकरण के रूप मे स्वीकारतें हैं जिसमें विभिन्न प्रविधियां एवं कार्य प्रणालियां समाविष्ट रहती है।

प्रत्येक विद्यालय के विद्यालयी रिकार्ड से छात्रों का नामांकन एवं उनसे ड्राप–आउट्स को गहराई से देखने के सन्दर्भ में ईकाई अध्ययन (केस स्टडी) विधि का प्रयोग प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत किया गया है, इन विधियों को समझ लेना आवश्यक है।

वर्तमान शोध आजमगढ़ जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट्स की समस्या का तुलनात्मक सर्वेक्षण दो प्रकार से किया गया है। पहला सर्वेक्षण विद्यार्थी स्तर पर, बालक–बालिका तथा जाति के आधार पर ड्राप आउट्स का विस्तार, कारण तथा परिणाम का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया गया है।

7. प्रतिदर्श चयनः

अध्ययन के लिए आजमगढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों के प्राथमिक विद्यालयों को चुना गया था। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण लॉटरी द्वारा विद्यालयों का चयन किया गया।

प्रस्तुत शोध प्राथमिक स्तर पर बच्चों के विद्यालय छोड़ने की समस्याओं का अध्ययन के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद छोड़ने वाले विभिन्न प्रकार के थमिक विद्या नयों, सरकारी, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अध्ययन चुना गया

8. प्रयुक्त सांख्यिकी –

शोधकर्ता ने इस अध्ययन में केवल पर्सेंटाइल वैल्यू को नियोजित किया है और किसी अतिरिक्त आंकड़े का उपयोग नहीं किया है। अपनी गाइडबुक में, शोधकर्ता ने स्कूल के आंकड़ों के आधार पर चुने हुए क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दर्ज की। प्राइमरी स्कूल के सभी पाठ्यक्रमों में ड्रॉपआउट पाए गए।

उसके बाद, ड्रॉप–आउट छात्रों के माता–पिता ने निर्धारित साक्षात्कार देखकर अपने बच्चों को उनकी शैक्षिक, आर्थिक, जाति, लिंग और धार्मिक स्थिति के आधार पर उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति से वर्गीकृत किया। इन उपकरणों के उपयोग के साथ, संख्या निर्धारित की गई थी, और प्रतिशत मूल्य की गणना की गई थी, साथ ही साथ छोड़ने वालों के कारणों की भी गणना की गई थी। इन कारणों पर ड्रॉप आउट के प्रतिशत मूल्य की गणना करने के लिए प्रत्येक कारण पर ड्रॉप आउट रिपीटर्स की संख्या का उपयोग किया गया था।

9. प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका संख्या 4.1

	ड्राप–आउटप्रतिशत में
कुल ड्राप–आउट	12.60
छात्रों का ड्राप–आउट	13.95
छात्राओं का ड्राप–आउट	10.76

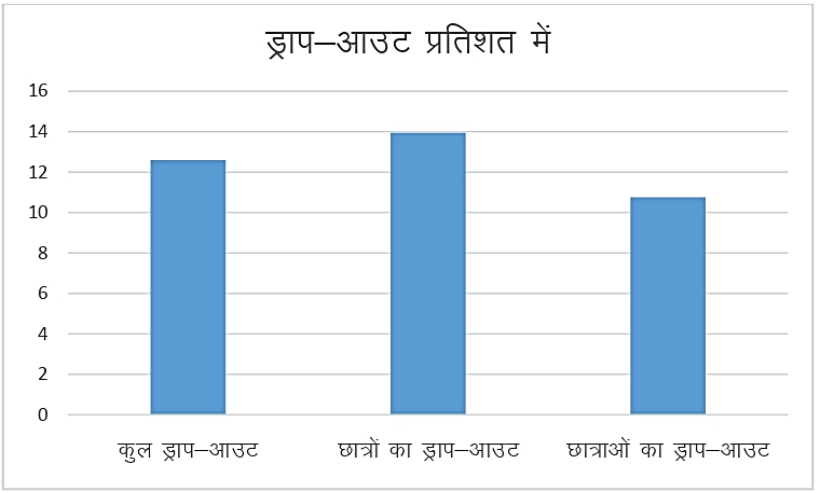

उपरोक्त तालिका को देखने से यह प्रतीत होता है कि कुल नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या 11297 है इसमें से ड्राप–आउट्स की संख्या 1424 है। जो कुल नामांकन का 12.60 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 4.2

	ड्राप–आउटप्रतिशत में
कक्षा 1	5.96
कक्षा 2	44.52
कक्षा 3	26.82
कक्षा 4	18.04
कक्षा 5	4.63

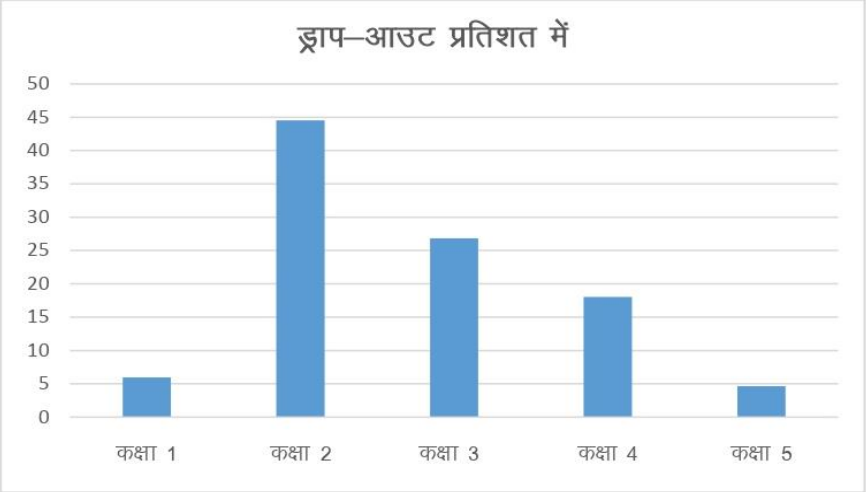

उपरोक्त तालिका 2 को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कुल ड्राप–आउट्स में से कक्षा एक में ड्राप–आउट 5.9 प्रतिशत कक्षा दो में 44.52 प्रतिशत कक्षा–तीन में 26.82 प्रतिशत कक्षा 4 में 18.04 प्रतिशत कक्षा पाँच में 4. 63 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 4.8

ड्राप आउट्स (पढ़ाई छोड़ देने वालों) के प्रमुख कारणों की एवं उन पर ड्राप – आउट्स की संख्या तथा प्रतिशतमान की तालिका :

क्रम संख्या	ड्राप आउट्स के कारण	प्रतिशतमान	नामांकन के सापेक्ष प्रतिशतमान
1	गरीबी के कारण	8.21	1.03
2	शिक्षकों की कमी के कारण	24.15	3.04
3	पारिवारिक अशिक्षा के कारण	5.54	0.69
4	पारिवारिक विग्रह के कारण	3.37	0.42

5	दुकान (पर कार्यरत)	3.16	0.39
6	कृषि (संलग्न होने पर)	4.98	0.62
7	परदेश गमन (पिता – अभिभावक)	5.89	0.74
8	मैकेनिक (कार्यों में संलग्न)	2.73	0.34
9	सिलाई (कार्य में सलग्न)	1.40	0.17
10	विद्यालय में पढाई का न होना	40.51	5.10

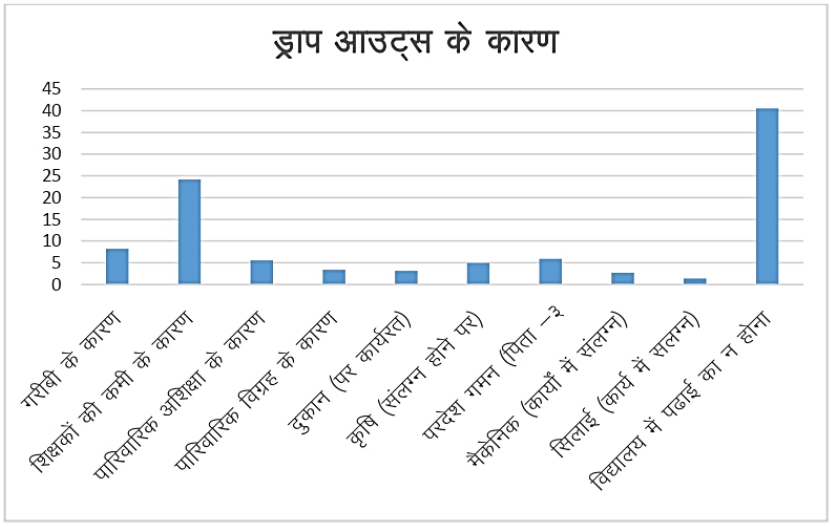

उपरोक्त तालिका 4.8 को देखने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट्स गरीबी के कारण 8.21 प्रतिशत शिक्षकों की कमी के कारण 24.15 प्रतिशत पारिवारिक अशिक्षा के कारण 5.54 प्रतिशत, पारिवारिक विग्रह के कारण 3.37 प्रतिशत, दुकान (पर कार्यरत) 3.16 प्रतिशत, कृषि (संलग्न होने पर) 4.98

देश के बाहर की गई यात्राओं का अनुपात (पिता 6 अभिभावक) 5.89 प्रतिशत मैकेनिक (काम में लगे हुए) 2.73 प्रतिशत, राउंडिंग (काम में लगे हुए) 1.40 प्रतिशत, स्कूल नहीं जाने वाले 40.50 प्रतिशत कुल नामांकन के एक

अंश के रूप में , और छोड़ने के कारणों का प्रतिशत, 1.03 प्रतिशत गरीबी दर और शिक्षकों की कमी 3.04 प्रतिशत परिवार में निरक्षरता के कारण, 0.96 प्रतिशत परिवार में अनुग्रह के कारण 0.42 प्रतिशत, दुकान 0.39 प्रतिशत, कृषि 0.62 प्रतिशत, अंतरराष्ट्रीय यात्रा 0.74 प्रतिशत, मैकेनिक 0.34प्रतिशत, सिलाई 0.17 प्रतिशत और स्कूल में शिक्षा की कमी 0.42 प्रतिशत। 0.51 प्रतिशत, सटीक होना।

निष्कर्ष एवं सुझाव

तर्क यह है कि परिवारों, समाजों और सरकारों को स्कूल छोड़ने वालों को गंभीरता से लेना चाहिए और यह गारंटी देनी चाहिए कि सभी बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा मिले।

आजादी के 55 साल हो चुके हैं। ड्रॉपआउट अब तक एक मुद्दा रहा है। यह चिंता का विषय है कि शासन पर ध्यान न देना एक व्यापक रणनीति का लक्षण है। इससे निजात पाने के लिए सरकार को कदम बढ़ाने होंगे। क्योंकि सरकार का उद्देश्य और दायित्व प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। शासन स्तर पर अनिवार्य नामांकन एवं प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए।

छोटे बच्चों के लिए यह सरकार के लिए 1 मील है। उचित पठन सुविधाओं और उपकरणों के साथ स्कूल को अपनी सीमा के भीतर संचालित करना होगा। बच्चों को स्कूल जाने और सीखने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ग्राम–गाँव वार्ड–वार्ड माता–पिता शिक्षकों द्वारा संपर्क किया जाना चाहिए। ताकि उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा सके। यदि माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं ले जाते हैं, तो उन्हें दंडित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण असामान्य है, फिर भी यह 100% ड्रॉपआउट की रोकथाम में सहायता करेगा।

यह संभव है कि सहायता उपलब्ध हो। इसके अलावा कक्षा एक में लिखित व मौखिक परीक्षा पूरी उपस्थिति को ध्यान में रखकर ली जाए।

मध्यम आय वाले माता–पिता के बीच अधिकांश ड्रॉपआउट वित्तीय चिंताओं के कारण होते हैं। आर्थिक तंगी के कारण बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं; ऐसे में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और युवाओं को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनके माता–पिता की आर्थिक मुश्किलें उन्हें अपनी शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर न करें। माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण

युवा अपनी शिक्षा नहीं छोड़ सकता है। संघीय स्तर पर, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस स्कूल भेजने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए एक सख्त तंत्र होना चाहिए।

हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की डिग्री वाले माता–पिता के बच्चों में ड्रॉपआउट अनपढ़ माता–पिता के बच्चों की तुलना में अधिक है, जो स्कूली शिक्षा के प्रति असंतोष और हाई स्कूल योग्य माता–पिता के बीच ज्ञान की कमी को दर्शाता है। इस हताशा को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए सार्वजनिक संगठनों और सरकारी प्रयासों द्वारा सफल प्रयास किए जाने चाहिए; दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यह प्रयास किया जाएगा, तभी ड्रॉपआउट पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए, अधिकांश विद्यालय अभी भी एकल–शिक्षक विद्यालय हैं; नतीजतन, माता–पिता अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल से वापस ले लेते हैं। यदि प्रत्येक स्कूल में कम से कम 5 प्रशिक्षक हों तो स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सकता है।

संदर्भ

- अली, ए। (2016)। बांग्लादेश में प्राथमिक स्कूल के छात्रों के बीच ड्रॉपआउट में योगदान करने वाले कारक। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 7(10), 89–96।
- चौधरी, आर. (2015). राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल के छात्रों के ड्रॉपआउट के लिए जिम्मेदार कारकों का एक अनुभवजन्य अध्ययन। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 20(4), 61–68।
- मिश्रा, एस। (2014)। प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट को प्रभावित करने वाले कारकरू भारत से साक्ष्य। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 5(8), 63–72।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2018)। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली। ीजजचरू/ /कपेम.हवअ.पद/ से लिया गया।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। (2015)। भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतकरू शिक्षा। http:@@mospi-nic-in@sites@default@files@publication&reports@KI&Education&71st&round-pdf से लिया गया।
- सिंह, ए., और सिंह, एस. (2016)। भारत में प्राथमिक स्कूल के छात्रों की ड्रॉपआउट समस्या पर एक अध्ययन। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 7(8), 10–16।

- स्वेन, एस., और बेहरा, एस. (2015)। ग्रामीण ओडिशा में प्राथमिक स्कूल ड्रॉपआउट को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन। मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 5(5), 11–20।
- यूनिसेफ। (2018)। भारत शिक्षा। https:@@www-unicef-org@india@education से लिया गया।
- यादव, एम.के., और खरे, एस. (2016)। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों पर एक अध्ययनरू भारत से साक्ष्य। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 7(22), 101–107।
- यूसुफजई, ए.के., रशीद, एमए, और भुट्टा, जेडए (2013)। वार्षिक शोध समीक्षारू संसाधन–सीमित सेटिंग्स में प्रारंभिक बचपन में प्रभावशाली और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को संबोधित करके सीखने के परिणामों में सुधार करना। जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री, 54(4), 402–412।
- झाई, एफ।, और डू, क्यू। (2014)। ऑनलाइन सीखने में छात्र ड्रॉपआउट को प्रभावित करने वाले कारक। जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, 17(4), 1–12।
- झू, एक्स।, चेन, वाई।, और यांग, वाई। (2016)। ग्रामीण चीन में बच्चों के बीच प्राथमिक स्कूल ड्रॉपआउट को प्रभावित करने वाले कारकरू एक तार्किक विश्लेषण। शैक्षिक विकास का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 24–33।
- जुल्फिकार, एफ।, और खान, एच। (2017)। ग्रामीण पंजाब में प्राथमिक विद्यालय छोड़ने की दर को प्रभावित करने वाले कारक। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 8(3), 104–109।
- यूनेस्को। (2016)। लोगों और ग्रह के लिए शिक्षारू सभी के लिए सतत भविष्य बनाना। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2016। पेरिसरू यूनेस्को।
- विश्व बैंक। (2018)। भारत अवलोकन। https:@@www-worldbank-org@en@country@india@overview से लिया गया।